

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का आर्थिक अध्ययन

Dr Lalit Mohan Singh

प्रधानाचार्य, स्वामी कृष्णानंद इण्टर कॉलेज जलाली, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

lalitmohansingh1586@gmail.com

मो0 9458513450

सारांश, भारत में पिछले चार दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की जांच उत्पादन और रोजगार की वृद्धि और संरचना के विश्लेषण के आधार पर की जाती है। 2004-05 के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी में कमी और गैर-कृषि गतिविधियों का प्रभुत्व देखा गया है। हालाँकि, कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। निर्माण क्षेत्र में रोजगार में काफी वृद्धि हुई, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं था कि कृषि छोड़ने वाले श्रमिकों को शामिल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप 2004-05 के बाद ग्रामीण रोजगार में गिरावट आई। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है, जिसके लिए विनिर्माण, सेवाओं और निर्माण में रोजगार सृजित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 68.8% आबादी और 72.4% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में शहरीकरण की ओर लगातार संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का हिस्सा घट रहा है। 2001 और 2011 के बीच भारत की शहरी आबादी में 31.8% की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण आबादी में 12.18% की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान शहरी आबादी में 50% से अधिक वृद्धि ग्रामीण-शहरी प्रवास और ग्रामीण बस्तियों के शहरी में पुनर्वर्गीकरण के कारण हुई। इसका विस्तार के साथ वर्णन मेरे इस शोध पत्र में किया गया है।

प्रस्तावना, 2004 के बाद, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में उच्च वृद्धि के बावजूद रोजगार में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। फिर हम नौकरियों में वृद्धि के उत्पादन में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखने के कारणों का पता लगाते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं और उत्पादन और रोजगार के बीच असममित परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। डेटा स्रोत ग्रामीण और शहरी शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी) के आंकड़े वर्ष 1970-71, 1980-81, 1993-94, 1999-2000, 2004-05 और 2011-12 के वर्तमान मूल्यों पर उपलब्ध हैं। विकास दर का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय उत्पादन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारों (2004-05=1) का उपयोग करके एनडीपी के नाममात्र मूल्यों को वास्तविक शब्दों में व्यक्त किया गया था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और रोजगार हिस्सेदारी के बीच विषमता

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति श्रमिक उत्पादकता में लगातार असमानता में परिलक्षित होती है। एक शहरी कर्मचारी ग्रामीण कर्मचारी की आय का लगभग तीन गुना या उससे अधिक कमाता रहा। 1999–2000 के बाद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी आई और यह शहरी अर्थव्यवस्था की विकास दर के बराबर हो गई। इससे कुल एनडीपी में ग्रामीण योगदान लगभग 48% पर स्थिर हो गया। विकास दर में तेजी के बावजूद 2004–05 से 2011–12 तक राष्ट्रीय एनडीपी में ग्रामीण हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए उच्च निर्भरता के गंभीर परिणाम हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच श्रमिक उत्पादकता में व्यापक असमानताएँ 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों ने विनिर्माण उत्पादन में 51.3% का योगदान दिया। हालांकि, उत्पादन में हिस्सेदारी में इस तेज वृद्धि से रोजगार हिस्सेदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके विपरीत, देश में कुल विनिर्माण रोजगार में ग्रामीण हिस्सेदारी 2011–12 से पहले के 40 वर्षों के दौरान 4.1 प्रतिशत अंकों से घट गई। स्पष्ट रूप से, विनिर्माण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रहा था, लेकिन रोजगार में समान वृद्धि नहीं हुई। इसी अवधि में, ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा कुल एनडीपी और कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा, और श्रमिक उत्पादकता में ग्रामीण-शहरी असमानता वर्ष अर्थव्यवस्था कार्यबल 2004–05 की कीमतों पर श्रमिक उत्पादकता (श्रमिक) ग्रामीण शहरी असमानता ये परिवर्तन यह संकेत करते हैं कि अपेक्षाकृत कम वेतन वाली निर्माण गतिविधियों में ग्रामीण रोजगार बहुत तेज दर से बढ़ा है। इन परिवर्तनों के अंतर्निहित कारणों और निहितार्थों पर शोध पत्र में चर्चा की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन 1970–71 से 2011–12 तक, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्यों पर 229 बिलियन से बढ़कर 34,167 बिलियन हो गई और 2004–05 की कीमतों पर 3,199 बिलियन से बढ़कर 21,107 बिलियन हो गई। इसी अवधि में, रोजगार 191 मिलियन से बढ़कर 336 मिलियन हो गया। इस प्रकार, ग्रामीण भारत में उत्पादन में लगभग सात गुना वृद्धि के बावजूद, चार दशकों की इस लंबी अवधि में रोजगार दोगुना भी नहीं हो सका। उत्पादन और रोजगार में वृद्धि दर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अवधियों में बड़े भिन्नताएं दर्शाती है, जो देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को समझने में उपयोगी है। तीन उप-अवधियों के दौरान एनडीपी और रोजगार में क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रस्तुत की गई है, और क्षेत्रीय संरचना 1970–71 से 1993–94 की अवधि में कृषि क्षेत्र के एनडीपी में 2.57% वार्षिक वृद्धि देखी गई, जबकि गैर-कृषि क्षेत्रों में 5.7% वार्षिक वृद्धि हुई परिणामस्वरूप, ग्रामीण एनडीपी में कृषि का हिस्सा 1993–94 तक 72.4% से घटकर 57% हो गया गैर-कृषि क्षेत्रों में, विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों ने क्रमशः 5.18%, 3.94% और 6.1% वार्षिक वृद्धि का अनुभव किया और ग्रामीण एनडीपी में उनका हिस्सा क्रमशः पूर्व-सुधार अवधि के दौरान 2.2 और 10 प्रतिशत अंकों से बढ़ा। सुधार के बाद की अवधि (1993–94 से 2004–05) के दौरान, कृषि क्षेत्र में वृद्धि धीमी होकर 1.87% हो गई, जबकि गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर बढ़कर 7.93% हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि में मंदी के प्रभाव को गैर-कृषि क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से उच्च वृद्धि द्वारा संतुलित किया गया, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास दर को पूर्व-सुधार अवधि के 3.72% की तुलना में 5% से ऊपर पहुंचा दिया। इन परिवर्तनों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी को 1993–94 में 57% से घटाकर 2004–05 में 39% कर दिया। इस प्रकार, 2004–05 तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि से अधिक गैर-कृषि बन गई। गैर-कृषि क्षेत्रों में, सेवा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों ने 2004-05 में ग्रामीण उत्पादन में क्रमशः 37.3%, 11.5% और 7.8% हिस्सेदारी का गठन किया

शोध पूर्व साहित्यिक अवलोकन

प्रधान 2013 जनसंख्या अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत 2050 तक मुख्य रूप से ग्रामीण बना रहेगा, जिसके बाद शहरी आबादी के ग्रामीण आबादी से आगे निकल जाने का अनुमान है (संयुक्त राष्ट्र 2012) अक्सर यह महसूस किया जाता है कि अनियोजित ग्रामीण से शहरी प्रवास, विशेष रूप से बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में, शहरी सुविधाओं पर गंभीर दबाव डाल रहा है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अनियोजित पलायन को रोकने और देश की अधिकांश आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार प्रति व्यक्ति ग्रामीण और शहरी आय में असमानता को कम करने के लिए भी आवश्यक है जो लगातार उच्च बनी हुई है। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से उच्च विकास की आवश्यकता है।

अग्रवाल और कुमार 2012 परंपरागत रूप से, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है। कृषि से अधिक उत्पादक गैर-कृषि क्षेत्रों में उत्पादन और व्यवसाय की संरचना में परिवर्तन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई विद्वानों ने देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा परिवर्तन हो रहा है।

मजूमदार और नीता श्रीवास्तव 2014 महिला एलएफपीआर में गिरावट का एक कारण शैक्षिक गतिविधियों में बढ़ी भागीदारी बताया गया है शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन को 2004-05 और 2011-12 के बीच सभी घरेलू प्रकारों में शिक्षा की श्रेणी में श्रम बल में नहीं महिला आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी से देखा जाता है घरेलू-प्रकारों में, कुल श्रम बल में नहीं महिला आबादी में शिक्षा की हिस्सेदारी में वृद्धि कर दी गई थी।

वैशम्पायन 2012 यह पत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की प्रकृति की जांच करता है और पिछले चार दशकों की अवधि में नौकरी सृजन और व्यवसाय संरचना पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। विभिन्न गैर-कृषि गतिविधियों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि में बेमेल के कारणों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। निष्कर्षों का उपयोग रोजगार-समर्थक ग्रामीण विकास रणनीति का सुझाव देने के लिए किया गया है। यह पत्र 1970-71 से भारत के कुल उत्पादन और रोजगार में ग्रामीण क्षेत्रों के बदलते योगदान पर चर्चा करता है। यह श्रमिक उत्पादकता में ग्रामीण-शहरी असमानता की प्रवृत्ति की जांच करता है और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन और रोजगार के ग्रामीण-शहरी वितरण में परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करता है। फिर यह पिछले चार दशकों के दौरान ग्रामीण उत्पादन और रोजगार के प्रदर्शन और बदलती संरचना पर अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है।

भारत में 2004–05 से 2011–12 के दौरान, कृषि क्षेत्र में पुनरुद्धार हुआ और इसने 4.27% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की। इसी तरह, गैर-कृषि क्षेत्रों की वृद्धि दर बढ़कर 9.21% हो गई। कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में वृद्धि में तेजी के आधार पर, इस अवधि को आर्थिक त्वरण की अवधि कहा जाता है। इस अवधि के दौरान समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि 7.45% थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस अवधि में गैर-कृषि कीमतों की तुलना में कृषि कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई, और वर्तमान कीमतों पर कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर लगभग समान थी। इसलिए, ग्रामीण एनडीपी में कृषि की हिस्सेदारी में और गिरावट नहीं आई और 2004–05 की तुलना में 2011–12 में यह 39.2% के मामूली उच्च स्तर पर रही। गैर-कृषि क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि 2004–05 के बाद घटकर 3.48% रह गई, जबकि पिछले दशक के दौरान यह 8.55% थी। 2004–05 और 2011–12 के बीच विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में क्रमशः 15.87% और 11.49% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई। परिणाम स्वरूप, इन सात वर्षों में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 37.3% से घटकर 27% हो गई, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी 11.4% से बढ़कर 18.4% हो गई और निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.8% से बढ़कर 10.5% हो गई। विभिन्न क्षेत्रों में विकास पैटर्न से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर काफी विविधीकरण पता चलता है।

आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, रोजगार में भी इसी तरह की प्रवृत्ति और पैटर्न परिलक्षित होना चाहिए। इसकी जांच उन वर्षों के अनुरूप एनएसएसओ दौर के रोजगार आंकड़ों से की गई, जिनके लिए राष्ट्रीय आय का ग्रामीण-शहरी वितरण प्रदान किया गया था, का अध्ययन करने से पता चलता है कि ग्रामीण रोजगार और उत्पादन में वृद्धि ने अलग-अलग पैटर्न का पालन किया। ग्रामीण रोजगार में सुधार-पूर्व अवधि के दौरान 2.16% वार्षिक वृद्धि दर देखी गई, जो सुधार-पश्चात अवधि में घटकर 1.45% हो गई और आर्थिक त्वरण की अवधि में नकारात्मक (0.28%) हो गई। उसी उप-अवधि में उत्पादन वृद्धि दर में तेजी आई। इस प्रकार, उत्पादन की तुलना में रोजगार में बहुत कम दर से वृद्धि हुई और 2004–05 के बाद उत्पादन में उच्च वृद्धि के मद्देनजर इसमें गिरावट भी आई। 2004–05 की कीमतों पर एनडीपी की वृद्धि दर और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार (%) अवधि कृषि विनिर्माण निर्माण सेवाएं गैर-कृषि कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर) ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीपी और रोजगार में क्षेत्रीय हिस्सेदारी, 1970 से 2012 (%) वर्ष कृषि विनिर्माण निर्माण सेवाएं ग्रामीण एनडीपी में हिस्सेदारी (वर्तमान मूल्यों पर)

ग्रामीण मामलों की समीक्षा आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक ईपीडब्ल्यू 30 दिसंबर, 2017 खंड संख्या 52 67 गैर-कृषि क्षेत्र कृषि छोड़ने वाले श्रम बल को अवशोषित नहीं कर सके। प्रस्तुत परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लोच समय के साथ कम हुई है और 2004–05 के बाद नकारात्मक हो गई है। रोजगार असंवेदनशील विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती आबादी और कृषि से बाहर जाने वाले कार्यबल को उत्पादक नौकरियां प्रदान करने की क्षमता पर गंभीर चिंता पैदा करता है। गैर-कृषि क्षेत्रों में, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि में मंदी का अनुभव किया गया था लेकिन निर्माण क्षेत्र में समय बीतने के साथ रोजगार विस्तार में तेज तेजी देखी गई। 2004–05 के बाद ग्रामीण रोजगार में

परिवर्तन यह पता लगाना उचित है कि 2004-05 और 2011-12 के बीच ग्रामीण कार्यबल में गिरावट बढ़ती बेरोजगारी के कारण थी या श्रम शक्ति में बदलाव के कारण थी। कार्यबल छोड़ने वाले लोगों की स्थिति और उन क्षेत्रों को जानना भी दिलचस्प होगा जहां ये परिवर्तन हुए।

इन पहलुओं का विश्लेषण श्रम बल भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यबल वितरण में घरेलू-प्रकार और लिंग-वार परिवर्तनों की जांच करके और 2004-05 और 2011-12 के बीच श्रम बल में नहीं आबादी की गतिविधि स्थिति को ट्रैक करके किया जाता है। उच्च उत्पादन वृद्धि और गिरते रोजगार (2004-05 से 2011-12) की अवधि के दौरान, ग्रामीण आबादी में 62 मिलियन की वृद्धि हुई, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच समान रूप से वितरित हुई जैसा कि श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) से संकेत मिलता है, श्रम बल में शामिल होने वाली पुरुष आबादी का अनुपात लगभग अपरिवर्तित (55%) रहा और 31 मिलियन वृद्धिशील पुरुष आबादी में से 16 मिलियन 2004-05 और 2011-12 के बीच श्रम बल में शामिल हुए। हालांकि, महिला श्रम बल की भागीदारी 2004-05 में 33% से 2011-12 में 25% तक उल्लेखनीय रूप से घट गई, जिसके परिणामस्वरूप महिला श्रम बल में 22 मिलियन की गिरावट आई। इससे 2004-05 और 2011-12 के बीच ग्रामीण श्रम बल (पुरुष, महिला) में लगभग 7 मिलियन की शुद्ध गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि एनएसएसओ डेटा ने इस अवधि के दौरान बेरोजगारी (सामान्य स्थिति के आधार पर) में कोई बदलाव नहीं दिखाया, और यह दिखाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल में श्रम बल के समान ही कमी आई यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के परिवारों में श्रम बल से महिला श्रमिकों की वापसी हुई है। 2004-05 और 2011-12 के बीच क्रमशः 8.49, 6.05 और 4.63 प्रतिशत अंकों से बढ़ाये साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि श्रम बल से महिला श्रमिकों की वापसी कृषि श्रमिक परिवारों में सबसे अधिक थी, उसके बाद कृषक और गैर-कृषि परिवार प्रतिशत और निरपेक्ष दोनों ही दृष्टि से थे। पुरुष श्रमिकों के मामले में, कार्यबल से वापसी केवल कृषि श्रमिक परिवारों में ही पाई गई। कई विद्वानों ने श्रम बल से महिलाओं के हटने के लिए प्रशंसनीय कारण बताए हैं।

कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिशत अंक जबकि गैर-कृषि परिवारों के लिए 1.4 प्रतिशत अंक। इसी तरह, शिक्षा में पुरुष "श्रम बल में नहीं" आबादी ने विचाराधीन अवधि के दौरान सभी प्रकार के घरों में पर्याप्त वृद्धि देखी। शिक्षा के लिए नामांकन में वृद्धि व्यक्तियों के शिक्षा स्तर और कौशल में सुधार के संदर्भ में एक वांछनीय प्रवृत्ति है। लेकिन असली चुनौती उन शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होगा जो निकट भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्रम बल में शामिल होते हैं। अधिकांश रोजगार के अवसर गैर-कृषि क्षेत्र में पैदा किए जाने हैं क्योंकि शिक्षित युवाओं की स्वाभाविक पसंद कृषि के बजाय अधिक उत्पादक गैर-कृषि क्षेत्रों में शामिल होना होगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि शिक्षा ने महिला श्रम बल में पूरी कमी का एक तिहाई हिस्सा लिया, जबकि श्रम बल (कृषि) से पुरुष समकक्षों की वापसी शिक्षा में वृद्धि के समान थी। श्रम बल से हटाई गई बड़ी संख्या में महिलाओं ने खुद को घरेलू गतिविधियों तक सीमित कर लिया, जैसा कि विचाराधीन अवधि के दौरान घरेलू गतिविधियों की श्रेणी में "श्रम बल में नहीं" महिला आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी से पता चलता है। कृषि कार्य से पीछे हटने वाली और घर पर ही रहने वाली महिलाओं के अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि कृषि श्रमिक परिवारों के

मामले में दर्ज की गई है। इसके अलावा, गैर-कृषि ग्रामीण परिवारों के मामले में भी घरेलू गतिविधियों में महिलाओं के अनुपात में वृद्धि देखी गई है।

भारत ने पहली बार कृषि में कार्यबल में कमी देखी। गिरावट की दर 2.04% थी। इसके बावजूद, कृषि ने कुल ग्रामीण कार्यबल के 64% को रोजगार दिया, जिन्होंने 2011-12 में कुल ग्रामीण उत्पादन का केवल 39% उत्पादन किया। यह अनुमान है कि कुल उत्पादन और रोजगार में कृषि के हिस्से के बीच अभिसरण लाने के लिए, 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्रों में 84 मिलियन कृषि श्रमिकों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। यह गैर-कृषि रोजगार में लगभग 70% वृद्धि के बराबर है, जो काफी चुनौतीपूर्ण दिखता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच श्रमिक उत्पादकता में बड़े अंतर का कारण है। कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर) केवल ₹30,912 थी इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्रों ने कृषि क्षेत्र की तुलना में 2.88 गुना अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान किया। 2004-05 के बाद कृषि कार्यबल में गिरावट के कारण, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच प्रति कर्मचारी उत्पादकता में असमानता प्रति वर्ष 1% कम हुई। विनिर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण उत्पादन ने 1970-71 और 1993-94 के बीच 5.18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की। सुधार के बाद की अवधि (1993-94 से 2004-05) में 8.38% की उच्च वृद्धि दर देखी गई, जो 2004-05 से 2011-12 के दौरान तेजी से बढ़कर 15.87% हो गई। अन्य क्षेत्रों की तुलना में विनिर्माण में उल्लेखनीय रूप से उच्च वृद्धि ने ग्रामीण एनडीपी में इसकी हिस्सेदारी 1970-71 में 5.9% से बढ़ाकर 2011-12 में 18.4% कर दी जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण की ओर एक स्पष्ट रुझान की ओर इशारा करता है। हालांकि, रोजगार ढांचे में बदलावों के जरिए औद्योगीकरण के संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। 1972-73 और 1993-94 के बीच, विनिर्माण क्षेत्र ने 10.29 मिलियन नौकरियां (वृद्धिशील गैर-कृषि नौकरियों का 29%) जोड़ीं और कुल ग्रामीण रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 1972-73 में 5.3% से बढ़कर 1993-94 में 7% हो गई। अगले दशक (सुधार के बाद की अवधि) के दौरान इस क्षेत्र ने 7 मिलियन नौकरियां (वृद्धिशील गैर-कृषि नौकरियों का 23.4%) जोड़ीं 2004-05 और 2011-12 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में मात्र 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निष्कर्ष, ग्रामीण भारत के बारे में मुख्य चिंता कृषि में कम उत्पादकता और कम वेतन वाले रोजगार पर उच्च निर्भरता के कारण प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है। ग्रामीण भारत में एक श्रमिक शहरी श्रमिक द्वारा उत्पन्न आय का एक तिहाई से भी कम उत्पन्न करता है। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में व्यापक असमानता बनी रही। अधिक चिंताजनक बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और निर्माण क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि के बावजूद ग्रामीण-शहरी असमानता में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब अधिक गैर-कृषि हो गई है और ग्रामीण आय में कृषि का हिस्सा घटकर 39% से भी कम हो गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखा गया दूसरा बड़ा परिवर्तन यह है कि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में इसका हिस्सा 1970-71 और 2011-12 के बीच दोगुना हो गया और शहरी क्षेत्रों से अधिक हो गया। हालांकि, इस परिवर्तन के साथ रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ और विनिर्माण रोजगार में

ग्रामीण हिस्सेदारी में गिरावट आई। विनिर्माण उत्पादन में 15% की वार्षिक वृद्धि दर रोजगार में 1% की भी वृद्धि करने में विफल रही, जिससे यह अवधि बेरोजगारी वृद्धि का एक क्लासिक मामला बन गई। इसके अलावा, ग्रामीण भारत में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार महिलाओं के खिलाफ मजबूत पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 अब्राहम, वी (2009) ग्रामीण भारत में रोजगार वृद्धि संकट से प्रेरित इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 44, नंबर 16, पीपी 97–104
- 2 अग्रवाल, ए और एन कुमार (2012) संरचनात्मक परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और गरीबी उन्मूलन भारत का मामला, विकास पत्र 1206, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय, नई दिल्ली।
- 3 एस के श्रीवास्तव (2014) ग्रामीण श्रम बाजार में परिवर्तन और कृषि के लिए उनका निहितार्थ, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 49, संख्या 10, पृष्ठ 47–54
- 4 एस राणा (2015) भारत में कृषि आय का अनुमान और विश्लेषण, 1983–84 से 2011–12, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 50, संख्या 22, पृष्ठ 139–45
- 5 कन्नन, के पी और जी रवींद्रन (2012) लापता श्रम बल की गणना और प्रोफाइलिंग, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 47, संख्या 6, पृष्ठ 77–80।
- 6 एन के और जे वी वैशम्पायन (2012) भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विकास और संरचनात्मक परिवर्तन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, खंड 6, संख्या 2, पृष्ठ 321–31।